



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270865
CG-DL-E-12032026-270865

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947

No. 49]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

(मामला संख्या: -सीवीडी (एसी)-01/2026)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के और थाईलैंड से निर्यातित "सच्चारिन" के आयात पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/01/2026-डीजीटीआर.—मैसर्स स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "स्वाति" कहा गया है) और मैसर्स ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड (जिसे इसके बाद "ब्लू जेट" कहा गया है) (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "आवेदक" कहा गया है) ने यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क(सब्सिडी वाली वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष यह तर्क देते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया है कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सच्चारिन" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयात पर लगाए गए इन प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों की थाईलैंड (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से "सच्चारिन" (जिसे इसके बाद "जांचाधीन उत्पाद" अथवा "पीयूआई" कहा गया है) के निर्यातों के माध्यम से प्रवंचना की जा रही है।

क. पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 26 मार्च 2024 को अधिसूचना संख्या 7/34/ 2023 - डीजीटीआर के माध्यम से चीन जन.गण. से सञ्चारिन के आयात पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। अंतिम जांच परिणाम चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सञ्चारिन के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हुए 27 नवंबर 2024 को जारी किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने 2025-सीमा शुल्क (सीवीडी) की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01, दिनांक 25 फरवरी 2025 द्वारा सिफारिश किए गए निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए। ये शुल्क अभी भी चीन से संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

- विचाराधीन उत्पाद "सञ्चारित" है (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है)। पिछली की गई जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच इस प्रकार थी:

"11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सभी रूपों में सञ्चारित" है। "सञ्चारित" एक गैर-पोषक स्वीटनर है और इसे गन्ने की चीनी के लिए कम कैलोरी विकल्प माना जाता है। मुख्य रूप से सञ्चारित दो प्रकार के होते हैं, यानी घुलनशील और अघुलनशील। बाजार की भाषा में घुलनशील सञ्चारित को सोडियम सञ्चारित कहा जाता है जबकि अघुलनशील सञ्चारित को सञ्चारित या सञ्चारित एसिड कहा जाता है। सञ्चारित दो भौतिक रूपों में निर्मित होता है, अर्थात् दानेदार और पाउडर। दानेदार रूप में सोडियम सैकरीन का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां सञ्चारित घुल जाएगा, पाउडर के रूप में जिसे जमीन पर लाया गया है और धार देकर सुखाया गया है, इसका उपयोग सूखे मिश्रणों और फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। यह पानी में थोड़ा घुलनशील है। सञ्चारित का अघुलनशील रूप कई दवा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। सञ्चारित का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जैसे कि खाद्य और पेय पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, टेबल टॉप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर, फार्मास्यूटिकल्स आदि। सञ्चारित के सभी रूप वर्तमान जांच के क्षेत्र में हैं।

12. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित किए गए अनुसार ही है। प्राधिकारी का मानना है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

13. मेश आकार के आधार पर उत्पाद की कीमत और लागत पर दावे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे तर्क को प्रमाणित करने वाला कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने इस संबंध में रिकॉर्ड पर उत्पादन की लागत और जाल आकार के चयन की प्रक्रिया का विवरण रखा है, जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि जाल आकार अंतिम उत्पाद की लागत या कीमत को प्रभावित नहीं करता है।

14. जहां तक आवेदकों के इस अनुरोध का संबंध है कि विचाराधीन उत्पाद में सभी प्रकार के सञ्चारित शामिल हैं, विशेष रूप से- घुलनशील सञ्चारित, सोडियम सञ्चारित तथा सञ्चारित का नमक तथा अघुलनशील सञ्चारित, प्राधिकारी सबसे पहले मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में दिए गए अपने विवरणों का उल्लेख करते हैं, जहां यह माना गया था कि घुलनशील सञ्चारित को बाजार की भाषा में सोडियम सञ्चारित कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए साहित्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सञ्चारित का नमक केवल सोडियम सञ्चारित और घुलनशील सञ्चारित के लिए एक अलग शब्द है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सञ्चारित का नमक भी सञ्चारित का एक रूप है। अतः, यह माना जाता है कि सञ्चारित का नमक भी सञ्चारित का एक रूप है, और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल है।

15. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सञ्चारित को एचएस कोड 29251100 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

16. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों के तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपरोक्त दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

17. प्राधिकारी का मानना है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

- विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क उपशीर्ष 29251100 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. जांचाधीन उत्पाद

4. जांचाधीन उत्पाद जो तथाकथित रूप से चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की प्रवंचना कर रहा है, थाईलैंड से निर्यातित सञ्चारिन है, जिसे "जांचाधीन उत्पाद" या "पीयूआई" भी कहा गया है। जांचाधीन उत्पाद को सीमा शुल्क उपशीर्ष 29251100 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी तरह से इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

5. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

6. यह आवेदन-पत्र स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। दो अन्य उत्पादक हैं जो संबद्ध संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात् एएस केमोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड और श्री वर्दायिनी केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने दायर किए गए आवेदन-पत्र का समर्थन किया है।
7. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, न ही वे चीन या थाईलैंड में किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है।

ड. तथाकथित प्रवंचना और उपचारात्मक प्रभाव कम करने का आधार:

8. मौजूदा प्रवंचनारोधी शुल्क को कथित तौर पर दरकिनार करते हुए थाईलैंड से पीयूआई पर लागू अधिसूचना संख्या 01/2025-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 25 फरवरी 2025 के अनुसार लगाए गए मौजूदा प्रवंचनारोधी शुल्क को बढ़ाए जाने की मांग करते हुए प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदनपत्र दायर किया गया है। आवेदकों ने प्रवंचनारोधी जांच की मांग करने के लिए कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सञ्चारिन के आयात पर लगाए गए प्रवंचनारोधी शुल्क की थाईलैंड से भेजे गए आयात के माध्यम से प्रवंचना की जा रही है।
- ख. यह दावा किया गया है कि फरवरी 2025 में चीन जन.गण. पर प्रवंचनारोधी शुल्क लगाने और थाईलैंड पर प्रवंचनारोधी शुल्क की समाप्ति के बाद व्यापार के पैटर्न में काफी परिवर्तन आया है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से बचने को छोड़कर व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के लिए कोई पर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य नहीं है।
- ग. थाईलैंड से सञ्चारिन का आयात कथित तौर पर अगस्त 2019 में चीन जन.गण. पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के बाद ही शुरू हुआ था, उसके बाद इसमें वृद्धि हुई, अक्टूबर 2022 में थाईलैंड पर प्रवंचनारोधी शुल्क लगाने के बाद इसमें गिरावट आई और थाईलैंड पर शुल्क बंद होने के बाद फिर से तेज हो गया।
- घ. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड से निर्यातित सञ्चारिन थाईलैंड में उत्पादित नहीं होता है, बल्कि चीनी मूल का होता है और केवल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए थाईलैंड के माध्यम से भेजा जाता है।
- ड. यह तर्क दिया गया है कि थाईलैंड में सञ्चारिन के लिए कोई वास्तविक विनिर्माण सुविधाएं नहीं हैं और पहचाना गया निर्यातक एक उत्पादक के बजाय एक व्यापारी/निर्यात गृह के रूप में काम करता है।
- च. आवेदकों ने पिछली प्रवंचनारोधी जांच के जांच परिणामों पर भरोसा किया है, जिसमें थाईलैंड से निर्यात चीनी मूल का होने का निष्कर्ष निकाला गया था जिसमें सब्सिडी वाले इनपुट शामिल थे।
- छ. आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि थाईलैंड से आयात कीमत चीन जन.गण. से आयात कीमतों से कम हैं। यह आरोप लगाया गया है कि थाईलैंड से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की कटौती करती हैं और यह कीमत कटौती प्रस्तावित जांच की अवधि में बढ़ गई है।

ज. आवेदकों ने दावा किया है कि थाईलैंड से आयात की मात्रा और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जो प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान घरेलू मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

9. आवेदकों ने थाईलैंड के माध्यम से सुरक्षित की गई पीयूआई पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पूर्व की तारीख से लगाए जाने का अनुरोध किया है।
10. आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि (i) व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन है जिसमें थाईलैंड से सञ्चारिन के आयात किसी पर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य के बिना 2024-25 वार जांच की अवधि में काफी अधिक स्तर तक बढ़ गए हैं और (ii) थाईलैंड से सञ्चारिन के ये आयात चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपाय के उपचारात्मक प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं।

च. जांच की शुरुआत

11. आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में दायर आवेदन-पत्र के आधार पर, थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयात द्वारा चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपायों की प्रवंचना का तर्क देते हुए और मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपायों के उपचारात्मक प्रभाव को कम करने वाले व्यापार की पद्धति में परिवर्तन के संबंध में स्वयं संतुष्ट होकर, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 27 के अनुसार इस जांच की शुरुआत की तारीख से चीन से आयातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर थाईलैंड से आयातित जांचाधीन उत्पादों में मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क बढ़ाए जाने पर विचार करने के लिए सीवीडी नियमावली के नियम 25 और 26 तथा अधिनियम की धारा 9(1)(i) के अनुसार प्रवंचनारोधी जांच शुरू करते हैं।

छ. शुल्क पूर्व तारीख से लगाना और अनंतिम मूल्यांकन की आवश्यकता

12. आवेदकों ने प्राधिकारी से नियम 27(1) के अनुसार प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पूर्वव्यापी की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश करने के लिए और नियमावली के नियम 26(4) के अनुसार अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया है। हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के अनुसार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
13. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नियमावली के नियम 26(4) के अनुसार इस समीक्षा के पूरा होने तक विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करते हैं।

ज. संबद्ध देश

14. इस प्रवंचना में शामिल संबद्ध देश थाईलैंड है।

झ. जांच की अवधि

15. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि अप्रैल 2025 -सितंबर 2025 (6 माह) पर विचार किया है। क्षति जांच की अवधि 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>). पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल - सीवीडी/एसी/19122025/01 पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कल्यात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
17. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
19. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल <https://setu.dgtr.gov.in> पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रभावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यपद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और

अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- सीवीडी/एसी/19122025/01 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए। या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें।
22. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
23. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
24. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष को गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करने की आवश्यकता है।
27. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
29. हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।
30. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।

31. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
32. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
33. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ढ. असहयोग

35. यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March 2026

(Case No. CVD(AC)- 01/2026)

Subject: Initiation of anti-circumvention investigation regarding countervailing duties imposed on imports of “Saccharin” originating in China PR and exported from Thailand.

F. No. 7/01/2026-DGTR.—M/s. Swati Petro Products Ltd. (hereinafter referred to as “Swati”) and M/s. Blue Jet Healthcare Ltd. (hereinafter referred to as “Blue Jet”) (hereinafter collectively referred to as the “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), contending that these countervailing duties imposed on imports of “Saccharin” (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR, are being circumvented by way of exports of “Saccharin” (hereinafter referred to as “product under investigation” or “PUI”) from Thailand (hereinafter referred to as the “subject country”).

A. Background

1. The Designated Authority on 26th March 2024, vide Notification No. 7/34/2023-DGTR, initiated the sunset review investigation of countervailing duties imposed on imports of Saccharin from China PR. Final findings recommending continuation of definitive countervailing duty on imports of Saccharin originating in or exported from China PR was issued on 27th November 2024. The Ministry of Finance vide Customs Notification No. 01 of 2025-Customs (CVD), dated 25th February 2025 imposed the definitive countervailing duties recommended. These duties are still in force on imports of the subject goods from China.

B. Product under Consideration

2. The product under consideration is “Saccharin” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under

consideration" or "PUC"). The product under consideration defined in the last concluded investigation, the sunset review investigation of countervailing duty was as under:

“11. The product under consideration in the present investigation is “Saccharin in all its forms”. “Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation.

12. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The Authority considers that the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the PUC in the present investigation.

13. With regard to the claim on price and cost of the product varying based on mesh size, the Authority notes that no evidence has been provided by the interested parties substantiating such argument. Further, the Applicants have placed on record in this regard, the cost of production and descriptions of the process of selecting mesh size, clearly establishing that the mesh size does not affect the cost or price of the final product.

14. As regards the Applicants submission that the product under consideration includes all forms of saccharin, and in particular- soluble saccharin, sodium saccharin, and the salt of saccharin, as well as insoluble saccharin, the Authority first refers to its statements in the final findings of the original investigation, where it was held that soluble saccharin is called sodium saccharin in market parlance. Further, from analysis of the literature placed on record by the Applicants, it is evident that salt of saccharin is merely a different term for sodium saccharin and soluble saccharin. It is thus evident that salt of saccharin is also a form of saccharin. Therefore, it is held that salt of saccharin is also a form of saccharin, and is included within the scope of the product under consideration in the present investigation.

15. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Saccharin is classified under HS Code 29251100. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

16. After considering the information on record, the Authority considers that there is no known difference in product under consideration exported from the subject country and the subject goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the subject goods exported from the subject country in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

17. The Authority holds that the subject goods produced by the Applicants are like article to the product under consideration exported from the subject country, in accordance with the Rules.”

3. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs subheading 29251100. The customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

C. Product under Investigation

4. The product under investigation which is allegedly circumventing the countervailing duty in force on imports of the product under consideration from China PR, is Saccharin exported from Thailand, also referred to as “product under investigation” or “PUI”. The PUI is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs subheading 29251100. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

D. Domestic Industry and Standing

5. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:
"domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or like article from other countries or are themselves importers thereof, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers."
6. The application has been filed by Swati Petro Products Ltd. and Blue Jet Healthcare Ltd. There are two other producers producing subject goods, namely, A. S. Chemopharma Pvt. Ltd. and Shree Vardayini Chemical Industries Pvt Ltd., who have supported the application filed.
7. The Applicants have claimed that they have not imported the subject goods from the subject country, nor are they related to any producer/exporter in China or Thailand or any importer in India. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. Grounds for Alleged Circumvention and Undermining Remedial Effect:

8. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing countervailing duty levied on the PUC vide Notification No. 01/2025- Customs (CVD) dated 25th February 2025 to the PUI from Thailand, allegedly circumventing the existing countervailing duty. The Applicants have furnished reasons/evidence for seeking anti-circumvention investigation which includes:
 - a. The Applicants have alleged that the countervailing duty imposed on imports of Saccharin originating in or exported from China PR is being circumvented through imports consigned from Thailand.
 - b. It is claimed that there has been a significant change in the pattern of trade following the imposition of countervailing duty on China PR and the cessation of anti-circumvention duties on Thailand in February 2025. It is alleged that there is no sufficient due cause or economic justification for the change in pattern of trade other than avoidance of countervailing duty.
 - c. Imports of Saccharin from Thailand reportedly commenced only after imposition of countervailing duty on China PR in August 2019, increased thereafter, declined following imposition of anti-circumvention duties on Thailand in October 2022, and have intensified again after cessation of duties on Thailand.
 - d. The Applicants have alleged that Saccharin exported from Thailand is not produced in Thailand but is of Chinese origin and merely routed through Thailand to avoid payment of countervailing duty.
 - e. It is contended that there are no genuine manufacturing facilities for Saccharin in Thailand and that the identified exporter operates as a trader/export house rather than a producer.
 - f. The Applicants have relied on findings of the previous anti-circumvention investigation, wherein exports from Thailand were concluded to be of Chinese origin incorporating subsidised inputs.
 - g. The Applicants have further contended that import prices from Thailand are lower than import prices from China PR. It is alleged that the landed price of imports from Thailand undercuts the selling price of the domestic industry and that such price undercutting has increased in the proposed POI.
 - h. The Applicants have claimed that imports from Thailand have increased in volume and market share, reaching a significant share of the domestic demand during the proposed POI.
9. The Applicants have requested retrospective imposition of countervailing duty on the PUI circumvented through Thailand.
10. The Authority, on the basis of the prima facie evidence provided by the Applicants notes that (i) there is a change in the pattern of trade wherein imports of Saccharin from Thailand have increased to a significant level in 2024-25 and the POI without any sufficient cause or economic justification and (ii) such imports of Saccharin from Thailand are undermining the remedial effects of the existing countervailing duty measure imposed on the PUC from China PR.

F. Initiation

11. On the basis of the application filed by the Applicants in the form and manner prescribed, contending circumvention of existing countervailing duty measures imposed on imports of the PUC from China PR by imports of the PUI from Thailand and having satisfied itself on the change in pattern of trade undermining the remedial effect of the existing countervailing duty measures, the Authority hereby initiates an anti-circumvention investigation in accordance with Section 9(1)(i) of the Act and Rules 25 and 26 of the CVD Rules to consider extension of the existing countervailing

duty on the imports of PUC imported from China to the PUI imported from Thailand from the date of initiation of this investigation in accordance with the Rule 27 of the Rules.

G. Retrospective Imposition of Duty and Need for Provisional Assessment

12. The Applicants have requested the Authority to recommend retrospective imposition of countervailable duty in accordance with Rule 27(1) and recommend provisional assessment in accordance with Rule 26(4) of the Rules. The interested parties may offer their comments in this regard as per the time limit given in this notification.
13. In view of the above, the Authority recommends provisional assessment of all imports of the product under consideration till completion of this review, in accordance with Rule 26(4) of the Rules

H. Subject Countries

14. The subject country involved in the circumvention is Thailand.

I. Period of Investigation

15. The Authority has considered the period of investigation from April 2025 – September 2025 (6 months) as proposed by the applicant. The injury investigation period has been considered as 2022-23, 2023-24, 2024-25, and the POI.

J. Submission of Information

16. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in/>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID- CVD/AC/19122025/01. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
17. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
18. Any other interested party may also make submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
19. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in/>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR www.dgtr.gov.in to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion /meeting schedule, notice of oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. Time Limit

20. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in/>) under their registered name and corresponding case ID- CVD/AC/19122025/01. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
22. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this Initiation Notification

23. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
24. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered

L. Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
27. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
30. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. Inspection of Public File

34. All non-confidential versions of submissions made by any interested parties will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. Non- Cooperation

35. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority